

## चुनाव आयोग के संदर्भ में नज़ी सदस्य वधियक

### प्रलिमिंस के लयि:

भारत नरिवाचन आयोग (ECI), अनुच्छेद 324, भारत की संचति नधि, इनर पार्टी डेमोक्रेसी

### मेन्स के लयि:

चुनाव आयोग की शक्तयिँ और ज़मिमेदारयिँ

## चर्चा में क्यौं?

हाल ही में देश में राजनीतिक दलों के आंतरिक संचालन को वनियिमति करने और नगरानी के लयि **भारत नरिवाचन आयोग (Election Commission-ECI)** को ज़मिमेदार बनाने के लयि लोकसभा में एक **नज़ी सदस्य वधियक** पेश कयिा गया ।

- यह वधियक ऐसे समय में प्रस्तुत कयिा गया है जब **सर्वोच्च न्यायालय**, **मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC)** और **चुनाव आयुक्तों** की नयुक्ति में सुधार की आवश्यकता पर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है ।
- यह तर्क दयिा गया था कि बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों की आंतरिक कार्यप्रणाली और संरचनाएँ बहुत "अपारदर्शी एवं जटलि" हो गई हैं तथा **और उनके कामकाज़ को पारदर्शी, जवाबदेह और नयिम आधारति बनाने की आवश्यकता है ।**

## नज़ी सदस्य वधियक

- संसद के ऐसे सदस्य जो **केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं हैं, को एक नज़ी सदस्य के रूप में जाना जाता है ।**
- नज़ी सदस्य वधियक का उद्देश्य सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षति करना है, जो **किसांसदों (मंत्रयिँ के अतरिकित) के मुताबकि, एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है** और जसिे वधियी हस्तक्षेप की आवश्यकता है ।
  - **इस प्रकार यह सार्वजनिक मामलों पर वपिक्षी पार्टी के रुख को दर्शाता है ।**
- सदन में इसे पेश करने के लयि एक महीने के नोटिस की आवश्यकता होती है **और इसे प्रस्तुत करने तथा इस पर चर्चा करने का कार्य केवल शुक्रवार को ही कयिा जा सकता है ।**
  - सदन द्वारा इसे अस्वीकृत कयिे जाने से सरकार में संसदीय वशिवास या उसके त्याग-पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।
- पछिली बार दोनों सदनों द्वारा एक नज़ी सदस्य वधियक 1970 में पारति कयिा गया था ।
  - यह 'सर्वोच्च न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्त्राधिकार का वसितार) वधियक, 1968' था ।

## वधियक की मुख्य वशिषताएँ:

- **CEC की नयुक्ति:**
  - यह प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, वपिक्ष के नेता या लोकसभा में सदन के नेता, वपिक्ष के नेता या राज्यसभा में सदन के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के दो वरषिठतम न्यायाधीश, से मलिकर बने एक पैनल द्वारा नयुक्ति कयिे जाने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त सहति चुनाव आयोग के सदस्यों की भी मांग करता है ।
- **CEC के लयि कार्यकाल:**
  - वधियक में **CEC और EC के लयि छह साल के नशिचति कार्यकाल** और क्षेत्त्रीय आयुक्तों के लयि नयुक्ति की तथिसिे तीन वर्ष के कार्यकाल की परकिलपना की गई है ।
- **CEC को हटाने की प्रक्रयिा:**
  - **सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लयि नरिधारति प्रक्रयिा के अलावा** उन्हें पद से हटया नहीं जा सकता ।
  - साथ ही, **सेवानवृत्तिके बाद, वे भारत सरकार, राज्य सरकारों और संवधिान के तहत कसिी भी कार्यालय में कसिी भी पुनरनयुक्ति के**

लघि पात्र नही होने चाहयि ।

■ गैर-अनुपालन की स्थितिमें प्रकरयि:

- यदकि कोई पंजीकृत राजनीतिक दल अपने आंतरकि कार्यों के संबंघ में ECI द्वारा जारी सलाह, व नरिदेशों का पालन करने में वफिल रहता है, तो **चुनाव चहिन (आरकषण और आवंटन) आदेश 1968** की धारा 16A के तहत ऐसे राजनीतिक दल की राज्य या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता चुनाव आयोग द्वारा वापस ली जा सकती है ।

## ECI की संरचना:

- मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त था लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधनियम, 1989 के बाद इसे एक बहु-सदस्यीय नकिय बना दयि गया है ।
- आयोग में एक CEC और दो EC होते हैं ।
  - भारत के राष्ट्रपति CEC और EC की नयिकृति करते हैं । इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है ।
  - वे भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं ।

## ECI की शक्तयिँ और कार्य:

- संसद के **परिसीमन** आयोग अधनियम के आधार पर देश भर में चुनाव नरिवाचन क्षेत्रों का नरिधारण करना ।
- मतदाता सूची तैयार करना और समय-समय पर संशोधति करना तथा सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना ।
- **राजनीतिक दलों को मान्यता** प्रदान करना और उन्हें चुनाव चहिन आवंटति करना ।
- आयोग के पास संसद और राज्य वधिनसभाओं के मौजूदा सदस्यों को **चुनाव के बाद अयोग्य ठहराने के मामले में सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी है ।**
- यह चुनावों के संचालन हेतु चुनाव कार्यक्रम तय करता है, **चाहे आम चुनाव हों या उपचुनाव ।**
- चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की आम सहमति से वकिसति **आदर्श आचार संहति** के सख्त पालन के माध्यम से राजनीतिक दलों के लघि चुनाव में समान अवसर सुनश्चिति करता है ।

## चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दे:

- **CEC का संकषपित कार्यकाल:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में टपिणी की क"वर्ष 2004 से कसी भी मुख्य नरिवाचन आयुक्त ने छह साल का कार्यकाल पूरा नहीं कयि है" और इस संकषपित कार्यकाल के कारण CEC कोई वशिष भूमकि नभाने में असमर्थ रहा है ।
  - संवधिन का **अनुच्छेद 324** नरिवाचन आयुक्त की नयिकृति का प्रावधान तो करता है, लेकिन इस संबंघ में वह केवल इस आशय के एक कानून के अधनियमन की परकिलपना करता है और इन नयिकृतयिँ के लघि कोई प्रकरयि नरिधारति नहीं करता है ।
- **नयिकृतिपर कार्यपालकि का प्रभाव:** नरिवाचन आयुक्तों की नयिकृतिविरतमान सरकार द्वारा की जाती है और इसलघि वे संभावति रूप से सरकार के प्रतिकृतज्ज होते हैं या उन्हें ऐसा लग सकता कि उन्हें सरकार के प्रतिकृत वशिषिट स्तर की नषिठा का प्रदर्शन करना है ।
- **वति के लघि केंद्र पर नरिभरता:** ECI को एक स्वतंत्र नकिय बनाने के लघि अभकिलपति वभिनिन प्रावधानों के बावजूद अभी भी इसके वति का नयित्रण केंद्र सरकार के पास है । नरिवाचन आयोग का वयय **भारत की संचति नधि** पर भारति नहीं रखा गया है ।
- **स्वतंत्र कर्मचारयिँ की कमी:** चूँकि ECI के पास स्वयं के कर्मचारी नहीं होते, इसलघि जब भी चुनाव आयोजति होते हैं तो उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारयिँ पर नरिभर रहना पड़ता है ।
- **आदर्श आचार संहति के प्रवर्तन के लघि सांवधिकि समर्थन का अभाव:** आदर्श आचार संहति के प्रवर्तन के लघि और नरिवाचन संबंधी अन्य नरिणयों के संबंघ में भारत नरिवाचन आयोग के पास उपलब्ध शक्तयिँ के दायरे एवं प्रकृति के बारे में स्पष्टता नहीं है ।
- **आंतरकि-पार्टी लोकतंत्र को वनियमति करने की सीमति शक्ति:** राजनीतिक दलों के आंतरकि चुनावों के संबंघ में ECI की शक्ति एवं भूमकि सलाह देने तक सीमति है और उसके पास **राजनीतिक दल के अंदर लोकतंत्र** को लागू करने या उनके वति को वनियमति करने का कोई अधिकार नहीं है ।

## आगे की राह

- **जस्टिस तारकूंडे समति (1975), दनिश गोस्वामी समति (1990), वधि आयोग (2015)** जैसी वभिनिन समतियिँ ने सफिरशि की है कि चुनाव आयुक्तों की नयिकृतिप्रधानमंत्री, लोकसभा में वपिकष के नेता और CJI की सदस्यता वाली समति की सलाह पर की जाए ।
- कार्यालय से हटाने के मामलों में ECI के सभी सदस्यों को समान संवैधानकि संरक्षण दयि जाना चाहयि । एक समरपति चुनाव प्रबंधन संवर्ग और कार्मकि प्रणाली लाना समय की मांग है ।

## UPSC सवलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

1. भारत का चुनाव आयोग पाँच सदस्यीय नकिय है ।
2. केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लघि चुनाव कार्यक्रम तय करता है ।
3. चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के वभिजन/वलिंय से संबंधति वविादों का समाधान करता है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिये ज़िम्मेदार है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान सभाओं और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों का संचालन करता है।
- मूल रूप से आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त था। वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त शामिल हैं। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- आयोग के पास मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवादों को नपिटाने की अर्द्ध-न्यायिक शक्ति निहित है। **अतः कथन 3 सही है।**
- यह चुनावों के संचालन के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है, चाहे आम चुनाव हों या उपचुनाव। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**
- **अतः विकल्प (d) सही है।**

प्रश्न. आदर्श आचार संहिता के विकास के आलोक में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2022)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/private-member-s-bill-on-election-commission)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/private-member-s-bill-on-election-commission>

